## विचार बिन्दु

**मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है।**
**–डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन**

# घटिया और नकली दवाओं के सेवन से खतरे में है आमजन की सेहत

देश में बनने वाली अंग्रेजी दवाएं पिछले कुछ सालों से अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में हैं। देश में आये दिन घटिया और नकली दवाओं के जखीरे पकड़े जा रहे है जो साबित करते है आमजन का स्वास्थ्य खतरे में है। आगरा में हाल ही नकली दवाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में करीब ढाई करोड़ रुपये की 2.97 लाख टैबलेट्स समेत आधा दर्जन नामी कंपनियों की दवाएं जब्त कीं गई। छापेमारी के दौरान एक दवा व्यापारी ने ड्रग विभाग के अफसरों को एक करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की। व्यापारी को तत्काल हिरासत में लिया गया। यह तो एक बानगी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की नियमित निगरानी गतिविधि के तहत जुलाई 2025 में खराब गुणवत्ता वाली और नकली दवाओं की सूची जारी की गई है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने इस दौरान 46 दवाओं के नमूनों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जबकि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 97 दवा नमूनों को मानक के अनुरूप न पाकर ख़राब गुणवत्ता वाली घोषित किया। इस प्रकार कुल 143 दवा नमूने जुलाई माह में असफल पाए गए। ये दवाएं अलग-अलग राज्यों से बाजार में उपलब्ध थीं और मरीजों तक पहुँच चुकी थीं। सूची में अधिकांश दवाएं मधुमेह, रक्तचाप, पेट की गैस और दर्द निवारक श्रेणी की हैं।

देशभर में आजकल घटिया, नकली और अमानन दवाओं का बाजार धड़ल्ले से पनप रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद देश में घटिया और नकली दवाओं पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा सकी है, जिसके कारण देश के लाखों लोगों की सेहत सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। भारत में नकली, घटिया और अवैध दवाओं का धंधा तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से रोगियों की जान जोखिम में है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो दवाएं धोखाधड़ी से निर्मित या पैक की गई हैं, उन्हें नकली और घटिया दवाएं कहा जाता है क्योंकि उनमें या तो सक्रिय अवयवों की कमी होती है या गलत खुराक होती है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीघ्र ही भारतीय दवा बाजार 60.9 अरब डालर के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी। आज के इस समय में नकली दवाइयां भी खूब मिलने लग गई हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बाजार में नकली दवाइयों की बिक्री बढ़ गई है। बाजारों-अस्पतालों में घटिया और नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नकली और घटिया दवाएं बनाने की सबसे अधिक कंपनियां हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से बहुत सी ऐसी कंपनियां सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई का ठेका लेती हैं। नकली दवाओं का सेवन करने से आपके शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन वेबसाइट से दवाओं को खरीदते हैं तो इस स्थिति में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। घटिया और नकली दवाओं को बनाना-बेचना भ्रष्टाचार ही नहीं हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ऐसे में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाकर ही नकली और मिलावटी दवाओं से निजात मिलेगी।

**गंभीर बीमारियों की छोड़िये, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, एसीडीटी, रक्तचाप और गैस आदि भी यदि अंग्रेजी दवाओं से ठीक नहीं हो रही है तो आप सावधान हो जाइये क्योंकि इन दवाओं के नकली और घटिया होने का खतरा मंडरा रहा है। अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया है कि देशभर में नकली और घटियां दवाओं का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है जिसका पुख्ता प्रमाण सरकारी एजेंसियों की छापामारी से मिल रहा है।**

गंभीर बीमारियों की छोड़िये, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, एसीडीटी, रक्तचाप और गैस आदि भी यदि अंग्रेजी दवाओं से ठीक नहीं हो रही है तो आप सावधान हो जाइये क्योंकि इन दवाओं के नकली और घटिया होने का खतरा मंडरा रहा है। अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया है कि देशभर में नकली और घटियां दवाओं का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है जिसका पुख्ता प्रमाण सरकारी एजेंसियों की छापामारी से मिल रहा है। जाँच में ये दवाइयां नकली निकल रही है जो जनता के स्वास्थ्य से सरेआम खिलवाड़ है। आम आदमी जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट की ख़बरों से खासा परेशान है। हमारे बीच यह धारणा पुख्ता बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली अंग्रेजी दवाओं में कुछ न कुछ मिलावट जरूर है। लोगों की यह चिंता बेबुनियाद नहीं है। ये दवाएं नामी ब्रांडेड कंपनियों की पैकेजिंग में बेची जा रही हैं।

देशभर में हर दूसरे या तीसरे दिन खबरें छपती रहती है कि इतने करोड़ की नकली दवाई पकड़ी गयी। इतनी दवाओं को नष्ट किया गया या सील किया गया। इसके बावजूद नकली दवाओं का धंधा बजाय कम होने के बढ़ता ही जा रहा है। नक़ली दवाएं या मिलावटी दवाएं वे होती हैं, जिनमें गोलियां, कैप्सूल या टीकों आदि में असली दवा नहीं होती, दवा की जगह चॉक पाउडर, पानी या महंगी दवा की जगह सस्ती दवा का पाउडर मिला दिया जाता है, इसके अलावा एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा पैक करके बेचने का धंधा भी होता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नकली दवाओं के उत्पादन और प्रसार का बाजार करीब 35 हजार करोड़ रुपए का है। इसी से यह समझा जा सकता है की देश में किस प्रकार नकली दवाओं का व्यापार निर्विघ्न रूप से फल-फूल रहा है। एसोचेम का दावा है कि बाजार में बिकने वाली हर 4 में से 1 दवा नकली है। आम आदमी के लिए इनके असली या नकली होने की पहचान बहुत मुश्किल है। कहा ये भी जा रहा है बीमारियों से इतनी मौतें नहीं हो रही है जितनी नकली दवाओं के सेवन से हो रही है।

**- अतिथि संपादक,**
**बाल मुकुन्द ओझा**
**वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार**

## राशिफल गुरूवार 4 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:44 तक, सौभाग्य योग दिन 3:22 तक, बव करण सायं 4:15 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 5:21 से मकर राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज वामन जयन्ती, हरिवा यश भाव, भुवनेश्वरी जयन्ती है। आज बन बधड़ी (सिन्धी समाज) का अबूझ मुहूर्त है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 7:45 तक, चर 10:52 से 12:26 तक, लाभ-अमृत 12:26 से 3:33 तक, शुभ 5:07 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:41

**मेष**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

**सिंह**

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। मन में बना हुआ भय दूर होगा।

**धनु**

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**वृष**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कन्या**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में बाहर जाना हो सकता है।

**मकर**

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

**मिथुन**
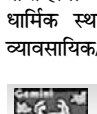
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

**तुला**
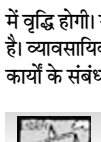
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**कुंभ**

व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

**कर्क**
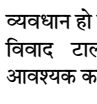
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

**वृश्चिक**
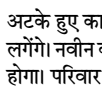
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मीन**
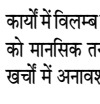
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

# कर सुधार की नई राह: जीएसटी, पेट्रोलियम और शराब नीति पर विमर्श

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कर दायरे में व्यापक सुधार की ओर संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मौजूदा दरों में बदलाव कर प्रणाली को ज्यादा सरल और सुगम बनाया जाएगा। यह घोषणा निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत, उपभोक्ताओं और राज्यों के लिए दूरगामी प्रभाव डालने वाली है।

भारत में कर व्यवस्था अक्सर जटिल और बहुस्तरीय रही है। जीएसटी लागू होने के बाद भी, इसके स्लैब यानी दरें लोगों के लिए उलझन का विषय बनी रहीं। वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसी कई दरों के चलते न सिर्फ आम जनता बल्कि कारोबारियों को भी भारी दिक्कतें आती हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में 28% और 12% दरों को खत्म कर शेष दरों को व्यवस्थित कर दे, तो यह 'वन नेशन, वन टैक्स' की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

जीएसटी स्लैब का सरलीकरण

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस दिशा में चर्चा होना जरूरी है कि जिन वस्तुओं पर 12% जीएसटी लगता है, उनमें से ज्यादातर आम उपभोग के खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और दैनिक जीवन की अन्य ज़रूरी वस्तुएँ हैं। इन्हें 5% के दायरे में लाने से महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

दूसरी ओर, 18% जीएसटी सर्विस सेक्टर पर अपेक्षाकृत भारी पड़ता है। बीमा, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और डिजिटल सेवाएँ इस श्रेणी में शामिल हैं। सामान्य परिवार के बजट में इन सबकी लागत बढ़ जाती है। कई अर्थशास्त्री यह सुझाव दे चुके हैं कि 12% और 18% की दरों को समेकित कर 15% का एक मध्यम स्लैब बनाया जाए। इससे कर-संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार भी नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी अनिवार्य सेवाओं को 5% के दायरे में लाना एक व्यावहारिक समाधान होगा। इन पर शून्य कर लगाना दीर्घकालिक रूप से समझदारी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सरकार को भी राजस्व चाहिए होता है। लेकिन इन सेवाओं की आमजन तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कर दर को न्यूनतम स्तर पर रखना अत्यंत आवश्यक है।

**पेट्रोलियम उत्पाद और ''वन नेशन, वन प्राइस'' की आवश्यकता**

भारत की ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। दुर्भाग्य से, इन पर अब तक जीएसटी लागू नहीं किया गया है और राज्यों की अलग-अलग दरों ने एक असमान कर व्यवस्था पैदा कर दी है। जिन राज्यों में करों की दरें अलग-अलग हैं, वहाँ उनके सीमा क्षेत्रों यानी बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंपों की बिक्री में स्पष्ट असमानता देखी जा सकती है। राज्यों के बीच दरों में इस भिन्नता के कारण न केवल उपभोक्ता कम दर वाले राज्यों की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि पेट्रोल और डीज़ल की तस्करी जैसी समस्याएँ भी जन्म लेती हैं। ऐसी स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की दरें समान हों ताकि न तो तस्करी को बढ़ावा मिले और न ही सीमा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को नुकसान उठाना पड़े।

यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और पूरे देश में एक समान दर तय हो, तो इससे दो बड़े लाभ होंगे-

1. लेवल प्लेइंग फील्ड: सभी उद्योगों और व्यवसायों को ऊर्जा एक समान कीमत पर मिलेगी जिससे प्रतिस्पर्धा में समानता आएगी।

2. राजस्व वितरण में पारदर्शिता: केंद्र सरकार अतिरिक्त कर लगाकर राज्यों को समुचित हिस्सा दे सकती है।

हां, यह सच है कि राज्यों को तत्काल राजस्व हानि उठानी पड़ सकती है, पर दीर्घकालिक दृष्टि से यह नुकसान नहीं बल्कि एक सतत समाधान है। केंद्र यदि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से राजस्व साझा करने की नीति बनाए, तो राज्यों का भरोसा भी बना रहेगा।

**गुणवत्ता और पर्यावरणीय दृष्टि से सुधार**

हां, यह सच है कि राज्यों को तत्काल राजस्व हानि उठानी पड़ सकती है, पर दीर्घकालिक दृष्टि से यह नुकसान नहीं बल्कि एक सतत समाधान है। केंद्र यदि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से राजस्व साझा करने की नीति बनाए, तो राज्यों का भरोसा भी बना रहेगा।

**गुणवत्ता और पर्यावरणीय दृष्टि से सुधार**

पेट्रोलियम जितना संवेदनशील विषय है, शराब नीति उससे भी अधिक विवादास्पद है। आज भारत में शराब की खपत तीव्र गति से बढ़ रही है। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को दरकिनार करते हुए यह उद्योग राजस्व हासिल करने का प्रमुख साधन बना हुआ है।

वास्तविक समस्या यह है कि शराब पर हर राज्य ने अपनी मनमानी दरें तय कर रखी हैं। कहीं-कहीं ऊंचे करों की वजह से तस्करी और अवैध शराब का व्यापार फल-फूल रहा है। कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि शराब माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार और टैक्स की चोरी जमकर होती है।

अगर जीएसटी काउंसिल साहस दिखाकर शराब की निर्माण लागत से लेकर एमआरपी तक एक समान दर तय कर दे, तो यह सिस्टम अधिक पारदर्शी हो जाएगा। सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा-जो पैसा भ्रष्टाचार और काले बाजार में जा रहा है, वह सरकारी खजाने में आएगा।

सामाजिक रूप से भी यह सुधार आवश्यक है। शराब की आसानी से उपलब्धता और दरों में असमानता न सिर्फ उपभोक्ताओं को गुमराह करती है बल्कि अवैध व्यापार को भी बढ़ावा देती है। यदि पूरे देश में एक समान दर लागू हो, तो शराब माफिया पर नियंत्रण होगा और समाज पर इसके नकारात्मक असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।

अगर जीएसटी काउंसिल साहस दिखाकर शराब की निर्माण लागत से लेकर एमआरपी तक एक समान दर तय कर दे, तो यह सिस्टम अधिक पारदर्शी हो जाएगा। सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा-जो पैसा भ्रष्टाचार और काले बाजार में जा रहा है, वह सरकारी खजाने में आएगा।

सामाजिक रूप से भी यह सुधार आवश्यक है। शराब की आसानी से उपलब्धता और दरों में असमानता न सिर्फ उपभोक्ताओं को गुमराह करती है बल्कि अवैध व्यापार को भी बढ़ावा देती है। यदि पूरे देश में एक समान दर लागू हो, तो शराब माफिया पर नियंत्रण होगा और समाज पर इसके नकारात्मक असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।

भारत को अब सवाल यह नहीं पूछना चाहिए कि ''क्या यह संभव है?'' बल्कि यह सोचना चाहिए कि ''इसे कब लागू करना है।''

धन्यवाद,

**रोटेरियन सुनील दत्त गोयल**
**महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री**
**पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड**
**जयपुर, राजस्थान**

# प्रकृति संरक्षण की लोक परम्पराओं में पलता समाज

डॉ. अरुणा व्यास

वर्षा से हमारे देश को प्रतिवर्ष करीब चार हजार अरब घन मीटर पानी मिलता है। विडम्बना की बात यह है कि लोक से जुड़ी परम्पराओं से दूर होने के कारण वर्षा जल संग्रहण के इस कार्य में सभी स्तरों पर उदासीनता आ रही है। इसी से वर्षा जल बड़ी मात्रा में सड़कों पर बहता भाप बनकर उड़ जाता है। हमारे यहां पारिस्थितिकी संतुलन के तहत अतीत की जल संचयन परम्परा में तालाबों की संस्कृति रही है। तालाब से गांव और जहां तालाब नहीं वहां गांव नहीं। गांव बसाना है तो तालाब पहले खुदेगा, फिर बसेगा गांव। यही नहीं अधिकांश गांवो का नाम ही तालाबों से जुड़ा रहा है। मसलन करमीसर, लूणकरणसर, किसमीदेसर, केसरदेसर, मलकीसर, रासीसर, बदरासर, भोमासर, जैतसर आदि-आदि। ये सभी गांवों के नाम हैं। यही नहीं सैंकड़ो-हजारों गांवों के साथ इसी तरह 'सर' जुड़ा हुआ है। 'सर' यानी सरोवर।

राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर सबसे गरम, सूखे इलाके हैं। देश के अन्य भागों में एक दिन में जितना पानी बरसता है, इन क्षेत्रों में वर्ष भर में बस उतना ही पानी बरसता है। आंकड़ों में कहें तो मात्र 3 से 12 इंच पानी ही इन सूखे क्षेत्रों में गिरता है, फिर भी यहां खेती होती रही है, धान उगता है और बहुत से गांवो में तो बगैर सरकारी प्रबंध के पानी की समुचित व्यवस्था भी वर्षों तक रही है। सोचिए! कैसे करते होंगे लोग पानी की यह व्यवस्था। लोक संस्कृति के अंतर्गत वर्षा पानी की एक-एक बूंद को सहेजते यहां के लोग जल को अमृत मानते रहे हैं। गांव के तालाब में आने वाला पानी कहीं बाधित नहीं हो, इसका ध्यान गांव का हर बाशिंदा रखता था। तालाब के चारों ओर ढ़ाल। जब कभी वर्षा होती, सभी स्थानों से बहकर पानी सीधे तालाब में ही जमा होता।...यह जमा पानी दिनों, महिनों तक तालाब में यूं ही जमा रहता और तो और कई कई स्थानों पर तो वर्षपर्यन्त तालाब पानी से भरे रहते। सोचिए! भूगर्भ जल के पानी का स्तर भी इससे क्या भरा-पूरा नहीं रहा है! इस प्रकार के और भी बहुत सारे तथ्य गांव की हमारी लोक संस्कृति के संदर्भ में प्रकाश में आए हैं जिनके अंतर्गत यहां की पारिस्थितिकी संतुलन में लोक की भागीदारी सीधे-सीधे रही है।

पारिस्थतिकी संतुलन के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। इसी के तहत राजस्थान में लोक परम्पराओं, विश्वास और संस्कृति से जुड़े पहलुओ में गोचर, ओरण और आगोर की परम्पराएं रही है। यह वह शब्द है जिनके तहत किसी वृच्छादित भूमि को गायों के चरने के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और फिर इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर वृक्ष नहीं काट सकता। गोचर भूमि पर वृक्ष काटने की मनाही के साथ ही उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं हो सकता। लोक से जुड़े विश्वास कुछ ऐसे रहे है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी-छुपे यहां पर वृक्ष कटाई का कार्य करता है तो उस पर कोई विपदा आन पड़ती है। इसी तरह ओरण भूमि की बात है। किसी मंदिर या धर्म स्थल के आस-पास बड़े स्तर पर भूमि का आरक्षण कर दिया जाता है। इस भूमि पर कहीं कोई वृक्ष नहीं काटा जाता, पशु वध नहीं किया जाता। ओरण भूमि का मतलब ही है देवता की भूमि। देवता की भूमि है इसलिए वहां पर पशु-पक्षियों पर अत्याचार नहीं किया जा सकता। पेड़ में भी चूंकि हमारी संस्कृति में जीव का वास बताया गया है, उसकी कटाई पर रोक रहती है। पारिस्थितिकी संतुलन के अंतर्गत राजस्थान में जो इस तरह की सामाजिक परम्पराएं रही हैं, उनकी आवश्यकता आज देशभर के परिप्रेक्ष्य में हैं। लोक से जुड़ी संवेदना के संस्कारों का यदि व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है तो उसकी परिणति में जलवायु परिवर्तन के खतरों का प्रभावी रूप में सामना नहीं किया जा सकता बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति से सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है, जो कि आज की आवश्यकता भी है।

लोक संस्कृति के संस्कार कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, इस बात के गवाह है-राजस्थान के विश्नोई समुदाय के प्रकृति सिद्धान्त। विश्नोई समुदाय अपने देवता जाम्भोजी द्वारा प्रदत्त सिद्धान्तों पर चलता है। उनके सिद्धान्तों में पेड़ काटने, जीव-जंतुओं का शिकार करने आदि पर पूरी तरह से वर्जना है। राजस्थान में कहावत भी है, 'सिर साटे रूंख, तो भी सस्तो जाण' यानी सिर के बदले यदि पेड़ कटता है तो वह भी सस्ता ही है। पेड़ नहीं काटने देने की सजा के रूप में कभी यहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अमृता देवी विश्नोई का पेड़ काटने जब राजा के सिपाही आगे बढ़े तो वह पेड़ के चिपक गई और अपना बलिदान दे दिया परन्तु पेड़ नहीं काटने दिया। इसी प्रकार विश्नोई समुदाय वन्यजीवों के शिकार का भी विरोध करता है। विश्नोई समुदाय में हिरणों के शिकार को सख्ती से रोका गया है। इसी कारण से हिरणों की कई प्रजातियां अभी भी बची हुई है।

**-डॉ. अरुणा व्यास,**
**पर्यावरण एवं संस्कृति अध्येता**
**स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक**

# घग्गर नदी में बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट

- **घग्गर नदी के जलस्तर की चौबीसों घंटे निगरानी, पानी की आवक को लेकर अधिकारी सतर्क**

**सूरतगढ़,** (निसं)। यहां से सटी घग्गर नदी में बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। एक दिन पूर्व एसडीएम की बैठक के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारी नाली बेड एरिया के बंधों और बहाव क्षेत्र का जायजा लेते नजर आए। स्वयं एसडीएम भरत जयप्रकाश मीणा ने तहसीलदार विनोद कड़वासरा के साथ रंगमहल गांव में पहुंचकर वर्ष 2023 में टूटे बंधे के स्थान का निरीक्षण कर सरपंच विजय सिंह ताखर से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली, वहीं नई और पुरानी बारेकां के बंधों का भी निरीक्षण किया।

सरपंच ताखर ने बताया कि एक दिन पूर्व ही उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से बंधे को मजबूत करवाने का काम शुरू किया है। ताकि पिछली बार जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं, सब रजिस्ट्रार विनोद गोदारा ने आरसीपी कॉलोनी के बंधे, 45 एसटीजी और फार्म एरिया के बंधों सहित बहाव क्षेत्र का निरीक्षण कर फार्म अधिकारियों और पटवारी से मौका स्थिति की जानकारी ली। नगर पालिका ईओ पूजा शर्मा ने बएयरफोर्स रोड पर स्थित पुल पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात करने के साथ ही आरसीपी कॉलोनी और अन्य स्थानों के बंधों पर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई है। उधर, एयरफोर्स रोड के पुल की कमजोर हालत को देखते हुए पीडब्लूयूडी विभाग ने पानी के अधिक बहाव होने पर पुल का उपयोग न करने की चेतावनी के बोर्ड लगवा दिए हैं। वहीं, मंगलवार को भी पुलों के बीच और किनारे फंसी केळीयों को निकालने में पोकलेन मशीन जुटी रही, ताकि बहाव में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। गिरदावर नरेंद्र बिश्नोई के मुताबिक पुलों से केळीयां हटाने के बाद बहाव तेज हो जाने से पीछे 45 एसटीजी इलाके में पानी का थोड़ा सा उतार देखा गया है। हालांकि, पिछले करीब एक सप्ताह से नाली बेड एरिया में एक समान 5000 क्यूसेक अपनी ही प्रवाहित हो रहा है। मगर पीछे हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में लगातार सक्रिय मानसून और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सिरसा के ओटू हेड से राजस्थान में पानी छोड़े जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, प्रशासन पूरी तरह चौकसी बरत रहा है। यहां तक कि सावधानी के तौर पर एसडीआरएफ की टीम को भी सूरतगढ़ बुला लिया गया है।

गौरतलब है कि मानसून के लगातार सक्रिय रहने से घग्गर नदी में संभावित बाढ़ की आशंका के चलते उपखंड अधिकारी आईएएस भरत जयप्रकाश मीणा ने सोमवार शाम को उपखंड कार्यालय में जल संसाधन विभाग, घग्गर बाढ़ नियंत्रण खण्ड, केंद्रीय राज्य फॉर्म, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, चिकित्सा, कृषि विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लेते हुए उन्हें चौबीसों घण्टे सतर्क रहने के निर्देश दिए थे।

जल संसाधन विभाग पीलीबंगा खंड के सहायक अभियंता अजीत पचार ने शाम के समय बताया कि मंगलवार सुबह गुल्लाचिका हेड पर 42,954 क्यूसेक पानी की मात्रा दर्ज की गई। वहीं, ओटू हेड पर 17,500 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। इसी तरह नाली बेड एरिया में पहले की तरह ही 5000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है। मंगलवार शाम को लिए गए गेज के मुताबिक पीछे गुल्लाचिका हेड पर पानी की आवक बढ़कर 44,484 क्यूसेक हो गई है, ओटू हेड और नाली बेड एरिया में गेज यथावत रहा।

एईएन पचार ने बताया कि गुल्लाचिका हेड पर बढ़ा हुआ पानी करीब 3 दिन बाद ओटू हेड पर नजर आएगा, जहां से यह पानी राजस्थान में ही छोड़ा जाएगा। हालांकि, वर्तमान स्थिति के मुताबिक खतरे जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी जिला प्रशासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारी अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग और घग्गर फ्लड से जुड़े अधिकारी लगातार पानी के बहाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

# घटिया सामग्री से हुए सड़क निर्माण कार्य की बरसात में पोल खुली

**भीलवाड़ा,** (निसं)। जिले मुख्यालय से मांडल के रास्ते आसींद की ओर जाने वाला हाइवे लंबे अरसे के बाद पूर्ण हो पाया, अभी इस हाइवे एनएच 158डी पर वाहनों को आवाजाही को शुरू हुए वक्त भी नहीं बिता कि घटिया साम्रगी से हुए निर्माण की पोल बरसात में खुल गई।

हरिपुरा चौराहे के पास बनी सर्विस लाइन इन दिनों लोगों को जख्म दे रही है, क्योंकि इस पर पहले से गड्ढे हैं और अब बारिश के बाद जमा पानी और कीचड़ से और अधिक हालात खराब हो गए हैं। पहले गड्ढे दिख जाते थे, लेकिन अब कीचड़ और पानी की वजह से देख नहीं पाते हैं और दोपहिया हो या चौपहिया वाहन चालक यह आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यहां कोई इकलौता हादसा हुआ हो। यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। इतने वाहन हादसे का शिकार हो चुके हैं कि पास के मैकेनिकों के पास एलुमीनियन की कई सारी नंबर प्लेट इकट्ठा हो गई है। इन लोगों का कहना है कि टोल नाके पर टोल लेने के लिए सब आगे रहते हैं लेकिन कोई भी सड़क को सही नहीं करता है। सुविधा के नाम पर टोल राशि तो वसूली जा रही है, लेकिन सुविधा के अभाव के चलते ना सिर्फ छोटे-बड़े वाहन चालक बल्कि कीचड़, टूटी सड़क और हादसे के बाद लगने वाले जाम से हरिपुरा के लोग भी काफी परेशान हैं और टोल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर हैं।